

पश्चिमी एशिया में शांति की तलाश: अरब-इजराइल संघर्ष, ऐतिहासिक प्रयास और वर्तमान चुनौतियाँ

सुमन भाखर¹, डॉ. सुलोचना²

¹शोधार्थी- राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजस्थान

²शोध निर्देशिका- सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.के. राजकीय महिला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान

शोध सारांश

यह शोध पत्र पश्चिमी एशिया (मध्य पूर्व) में स्थायी शांति की स्थापना और अरब-इजराइल संघर्ष के बहुआयामी आयामों का एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ यह भू-राजनीतिक एवं जातीय-राष्ट्रीय संघर्ष न केवल इस क्षेत्र के स्थायित्व को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय संतुलन के लिए भी गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 1948 में इजराइल के गठन से लेकर 1956, 1967 और 1973 के युद्धों, तथा तत्पश्चात हुए प्रमुख कूटनीतिक प्रयासों का ऐतिहासिक व आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। शोध में 1978 के कैम्प डेविड समझौते, 1993 के ओस्लो समझौते, 2002 की अरब शांति पहल और 2020 के अब्राहम एक्कोर्ड्स की सफलताओं और विफलताओं की पड़ताल की गई है। इसके साथ ही, यह पत्र 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' के समक्ष उत्पन्न गत्यावरोध, यरूशलेम की विवादित स्थिति, वेस्ट बैंक में अवैध इजराइली बस्तियों के विस्तार, और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या का विस्तृत विश्लेषण करता है।

अध्ययन में यह भी विश्लेषित किया गया है कि कैसे गैर-राज्य कलाकारों (Non-State Actors) जैसे हमास और हिजबुल्लाह की सैन्य भूमिका तथा ईरान-इजराइल के मध्य क्षेत्रीय वर्चस्व की छद्म जंग ने शांति वार्ता की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया है। अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे सऊदी अरब, मिस्र, कतर) की बदलती भूमिकाओं का परीक्षण करते हुए यह शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि केवल आर्थिक या सुरक्षात्मक समझौतों के माध्यम से फिलिस्तीनी अधिकारों की उपेक्षा करके स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। अंत में, यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय कानून, मानव अधिकारों और 1967 की सीमाओं के आधार पर एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य तथा सुरक्षित इजराइल के निर्माण हेतु व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द- पश्चिमी एशिया, अरब-इजराइल संघर्ष, ओस्लो समझौता, कैम्प डेविड समझौता, भू-राजनीति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहूदी बस्तियाँ, संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता

परिचय

पश्चिमी एशिया, जिसे वैश्विक कूटनीति में 'मध्य पूर्व' कहा जाता है, सर्वदा से मानव सभ्यता, तीनों प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों (इसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म) के उद्गम और व्यापारिक मार्गों का चौराहा रहा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यह क्षेत्र एक अभूतपूर्व और अंतहीन द्वंद्व का केंद्र बना हुआ है, जिसे 'अरब-इजराइल संघर्ष' के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष केवल दो जातीय या धार्मिक समूहों के मध्य का विवाद

नहीं है, बल्कि यह संप्रभुता, राष्ट्रीय पहचान, ऐतिहासिक दावों, और वैश्विक महाशक्तियों की कूटनीतिक रस्साकशी का एक अत्यंत जटिल मिश्रण है।

इस संघर्ष के बीच ऑटोमन साम्राज्य के पतन और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश मंडेट के दौरान बोए गए थे। 1917 की बालफोर घोषणा ने फिलिस्तीन की भूमि पर यहूदियों के लिए एक 'राष्ट्रीय गृह' स्थापित करने का समर्थन किया, जिसने यूरोप में यहूदी-विरोधी उत्पीड़न (Anti-Semitism) से भाग रहे यहूदियों के आव्रजन को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय अरब आबादी और यहूदी प्रवासियों के बीच संसाधन और भूमि पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए “होलोकॉस्ट” ने यहूदी राष्ट्र की मांग को वैश्विक सहानुभूति दिलाई, जिसके परिणति स्वरूप 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विभाजन प्रस्ताव 181' पारित किया गया। 1948 में इजराइल के निर्माण की घोषणा के साथ ही पहला अरब-इजराइल युद्ध छिड़ गया, जिसने इस क्षेत्र में हिंसा, विस्थापन और अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत की।

विगत सात दशकों में, अरब-इजराइल संघर्ष केवल इजराइल और उसके पड़ोसी अरब राज्यों (मिस्र, सीरिया, जॉर्डन) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का मुद्दा प्राथमिक केंद्र बन गया। 1967 के 'छह-दिवसीय युद्ध' ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट्स पर इजराइल का सैन्य कब्जा स्थापित कर विवाद के आयामों को और विकराल बना दिया। यद्यपि 1970 के दशक के बाद कूटनीति का दौर शुरू हुआ और मिस्र तथा जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति संधियाँ कीं, लेकिन मूल प्रश्न—अर्थात् फिलिस्तीनी जनता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र का निर्माण—अनुत्तरित ही रहा।

21वीं सदी में पश्चिमी एशिया की भू-राजनीति अधिक जटिल हो गई है। शीतयुद्ध कालीन सोवियत-अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता का स्थान अब बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था, ईरान-इजराइल छद्म युद्ध, और गैर-राज्य कलाकारों की रणनीतिक उपस्थिति ने ले लिया है। 2020 में हस्ताक्षरित 'अब्राहम एकोर्ड्स' ने कुछ अरब देशों (संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को) और इजराइल के मध्य आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों का सामान्यीकरण किया, किंतु इसने फिलिस्तीनी मुद्दे को हाशिये पर धकेल दिया। हालिया गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय तनावों ने यह साबित कर दिया है कि फिलिस्तीन समस्या का न्यायसंगत समाधान निकाले बिना पश्चिमी एशिया में कोई भी शांति प्रक्रिया दीर्घकालिक या स्थायी नहीं हो सकती। प्रस्तुत शोध पत्र इसी ऐतिहासिक परिदृश्य, कूटनीतिक वार्ताओं की समीक्षा और समकालीन चुनौतियों के आधार पर शांति की संभावनाओं की खोज करता है।

शोध के उद्देश्य

- अरब-इजराइल संघर्ष के ऐतिहासिक कारणों, रणनीतिक महत्व और 1948 से 1973 तक हुए प्रमुख युद्धों का आलोचनात्मक परीक्षण करना।
- फिलिस्तीनी प्रश्न की प्रकृति, शरणार्थी संकट, और भूमि अधिकार के कानूनी व मानवीय पहलुओं का अध्ययन करना।
- अतीत में किए गए प्रमुख शांति प्रयासों (कैम्प डेविड, ओस्लो समझौते, अब्राहम एकोर्ड्स) की सफलताओं और संरचनात्मक सीमाओं का मूल्यांकन करना।
- वैश्विक महाशक्तियों (अमेरिका, रूस, यूएन) और क्षेत्रीय खिलाड़ियों (ईरान, सऊदी अरब, मिस्र) की रणनीतिक भूमिका का विश्लेषण करना।
- समकालीन चुनौतियों (बस्तियों का विस्तार, गैर-राज्य समूह, आंतरिक विभाजन) की पहचान करते हुए 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा

अरब-इजराइल संघर्ष और पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया पर वैश्विक स्तर पर व्यापक और समृद्ध अकादमिक साहित्य उपलब्ध है। विभिन्न इतिहासकारों, कूटनीतिज्ञों और राजनीतिक शास्त्रियों ने इस विषय को यथार्थवादी, ऐतिहासिक, मानवाधिकारवादी और संस्थागत दृष्टिकोणों से विश्लेषित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में पाँच अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रन्थों का गहन आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है:

एवी श्लाइम – द आयरन वॉल: इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड (2001)- 'न्यू हिस्टोरियंस' धारा के प्रमुख इजराइली इतिहासकार एवी श्लाइम ने अपनी पुस्तक में इजराइल की सुरक्षा और विदेश नीति का विश्लेषण ज़ेव जाबोतिंस्की के "आयरन वॉल" (लोहे की दीवार) के सिद्धांत के आधार पर किया है। श्लाइम का तर्क है कि इजराइल के संस्थापकों ने यह रणनीति अपनाई थी कि जब तक अरब जगत सैन्य रूप से यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वे इजराइल को नष्ट नहीं कर सकते, तब तक कोई वास्तविक बातचीत संभव नहीं है। श्लाइम का मानना है कि यद्यपि इस सैन्य रणनीति ने इजराइल को सुरक्षित किया, लेकिन इसने इजराइली नेतृत्व को एक ऐसे रवैये में डाल दिया जहाँ वे कूटनीतिक रियायतों और शांति वार्ताओं को कमजोरी मानते हैं। शोध के संदर्भ में यह पुस्तक यह दर्शाती है कि अत्यधिक सैन्य-केंद्रित नीतियां दीर्घकालिक शांति के मार्ग में अविश्वास की स्थायी दीवार खड़ी करती हैं।

एडवर्ड सेड – द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजेशन (1994)- विख्यात विद्वान और सांस्कृतिक आलोचक एडवर्ड सेड ने फिलिस्तीनी परिप्रेक्ष्य को वैश्विक अकादमिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने इस पुस्तक में फिलिस्तीनियों के विस्थापन, उनकी भूमि बेदखली और उनकी राष्ट्रीय पहचान के दमन का विस्तृत ब्यौरा दिया है। सेड ने 1993 के ओस्लो समझौते की तीखी आलोचना की थी और इसे 'फिलिस्तीनी आत्मसमर्पण की संधि' करार दिया था। उनका तर्क था कि ओस्लो समझौते ने इजराइली कब्जे को समाप्त करने के बजाय उसे एक प्रशासनिक संरचना दे दी और फिलिस्तीनी अधिकारों के मुख्य प्रश्नों (जैसे यरूशलेम, शरणार्थियों की वापसी का अधिकार) को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। यह पुस्तक प्रस्तुत अध्ययन को मानवाधिकारों और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के दृष्टिकोण से शांति वार्ताओं का गंभीर मूल्यांकन करने का आधार देती है।

मार्क टेसलर – ए हिस्ट्री ऑफ द इजराइली-पैलिस्टिनियन कॉन्फ्लिक्ट (2009)- मार्क टेसलर का यह ग्रंथ इस विषय का सबसे निष्पक्ष, व्यापक और वस्तुनिष्ठ दस्तावेज माना जाता है। टेसलर ने इस बात पर बल दिया है कि यह संघर्ष बुनियादी रूप से धर्म का युद्ध नहीं है, बल्कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार का दावा करने वाले दो अलग-अलग राष्ट्रीय आंदोलनों (जायनिज्म और फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद) का टकराव है। टेसलर ने 19वीं सदी के अंत से लेकर 21वीं सदी तक की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक शोध पत्र के ऐतिहासिक अध्यायों को तटस्थता और संतुलन प्रदान करती है, जिससे दोनों पक्षों के आंतरिक अंतर्विरोधों को समझा जा सके।

चार्ल्स ए. कपचान – हाउ एनिमीज मेक पीस (2010)- अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर चार्ल्स कपचान ने अपनी पुस्तक में इस बात का सूक्ष्म अध्ययन किया है कि किस प्रकार सदियों पुराने दुश्मन देश अपनी शत्रुता भुलाकर शांति की राह चुनते हैं। उन्होंने 1978 के कैम्प डेविड समझौते (मिस्र-इजराइल) को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ रियायतें देकर सुरक्षा हासिल की गई। कपचान का तर्क है कि कूटनीतिक सफलता के लिए दोनों पक्षों में राजनीतिक जोखिम लेने वाला मजबूत नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ (जैसे अमेरिका) की प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। उनका यह ढांचा शोध में यह विश्लेषण करने में मदद करता है कि क्यों कैम्प डेविड की सफलता ओस्लो या अब्राहम एक्काईस में पूरी तरह नहीं दोहराई जा सकी।

ट्रिटा पारसी – ट्रेजरस अलायंस: द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड द यूएस (2007)- ट्रिटा पारसी की यह कृति यह समझने के लिए अनिवार्य है कि 21वीं सदी में अरब-इजराइल संघर्ष कैसे ईरान-इजराइल क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से जुड़ गया है। पारसी स्पष्ट करते

हैं कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद, ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी विदेश नीति का मुख्य हथियार बनाया ताकि वह अरब-मुस्लिम दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्लाह जैसे गैर-राज्य समूहों का वित्तपोषण और इजराइल की प्रतिक्रिया ने इस संघर्ष को द्विपक्षीय से क्षेत्रीय युद्ध में बदल दिया है। यह पुस्तक शोध पत्र के समकालीन भू-राजनीतिक विश्लेषण को गहराई प्रदान करती है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। शोध का उद्देश्य अरब-इजराइल संघर्ष के ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र और शांति वार्ताओं की संरचनात्मक सीमाओं को उजागर करना है।

- **द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग:** अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रतिष्ठित पुस्तकों, पीयर-रिव्यूड (Peer-reviewed) अकादमिक जर्नल्स (जैसे *Journal of Palestine Studies*, *Foreign Affairs*, *Middle East Journal*), तथा वैश्विक थिंक-टैंकों (Carnegie Endowment, Chatham House, SIPRI) की रिपोर्टों का व्यापक उपयोग किया गया है।
- **प्राथमिक दस्तावेजों का आलोचनात्मक विश्लेषण:** ऐतिहासिक संधियों और प्रस्तावों के मूल पाठ का विश्लेषण किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 (1967) एवं प्रस्ताव 338 (1973), कैम्प डेविड समझौता (1978), ओस्लो समझौते (I व II), अरब शांति पहल (2002) और अब्राहम एक्कोर्ड्स (2020) शामिल हैं।
- **विश्लेषणात्मक ढांचा:** शोध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 'यथार्थवादी सिद्धांत' (शक्ति संतुलन और सुरक्षा अनिश्चितता को समझने हेतु) और 'उदारवादी संस्थागत सिद्धांत' (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता व संधियों के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु) के संयुक्त मॉडल का प्रयोग किया गया है।

मुख्य विश्लेषण

पश्चिमी एशिया का भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक महत्व

पश्चिमी एशिया का वैश्विक मानचित्र पर एक अनूठा भू-राजनीतिक स्थान है। यह तीन महाद्वीपों—एशिया, यूरोप और अफ्रीका—के संधि-स्थल पर स्थित है। रणनीतिक दृष्टि से, यहाँ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य और समुद्री मार्ग स्थित हैं, जैसे सुएज नहर, बाब-अल-मंदेब और हॉर्मुज की जलसंधि। इन मार्गों से होकर विश्व का एक-तिहाई कच्चे तेल का व्यापार और महत्वपूर्ण कंटेनर शिपिंग गुजरती है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र दुनिया के ज्ञात हाइड्रोकार्बन (तेल और प्राकृतिक गैस) के विशालतम भंडारों का घर है। इसलिए, पश्चिमी एशिया में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष या अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक तेल बाजार, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains) और मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक रूप से, शीतयुद्ध के काल से ही यह क्षेत्र महाशक्तियों के लिए 'ग्रेट गेम' का अखाड़ा रहा है, जहाँ रणनीतिक अड्डों, हथियारों की बिक्री और भू-राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने की होड़ बनी रहती है।

अरब-इजराइल संघर्ष का इतिहास एवं युद्धों का दौर (1948 - 1973)

1. 1948 का प्रथम अरब-इजराइल युद्ध

14 मई 1948 को जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हुआ, डेविड बेन-गुरियन ने स्वतंत्र इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। इसके अगले ही दिन पांच अरब देशों (मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक) ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। सैन्य रूप से अधिक संगठित इजराइली सेना ने अरब देशों को पराजित कर दिया।

- **परिणाम:** संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की तुलना में इजराइल ने 23% अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया।
- **नकबा:** लगभग 7,00,000 से अधिक फिलिस्तीनी अरबों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ा, जिसने आज तक चले आ रहे विकराल 'फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट' को जन्म दिया।

2. 1956 का स्वेज संकट

जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल के साथ एक गुप्त समझौता करके मिस्र पर हमला किया। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में इजराइल को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि इजराइल इस क्षेत्र की एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन चुका है और पश्चिमी शक्तियां उसका समर्थन कर रही हैं।

3. 1967 का छह-दिवसीय युद्ध

यह युद्ध अरब-इजराइल संघर्ष का सबसे बड़ा मोड़ने वाला बिंदु साबित हुआ। इजराइल द्वारा किए गए पूर्व-नियोजित हवाई हमले में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की वायु सेनाएं तबाह हो गईं। मात्र छः दिनों में इजराइल ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया:

- मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी
- जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम
- सीरिया से गोलन हाइट्स

इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ऐतिहासिक प्रस्ताव 242 पारित किया, जिसने "शांति के लिए भूमि" के सिद्धांत की नींव रखी—अर्थात् इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस हटे और अरब देश इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार करें।

4. 1973 का योम किप्पुर युद्ध

1967 की हार का बदला लेने और अपनी खोई हुई भूमि वापस पाने के लिए मिस्र और सीरिया ने यहूदी पवित्र दिवस 'योम किप्पुर' के दिन इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआती झटकों के बाद इजराइल ने अमेरिकी मदद से वापसी की। यद्यपि सैन्य रूप से युद्ध बेनतीजा रहा, लेकिन इसने इजराइल के 'अजेयता' के भ्रम को तोड़ दिया और दोनों पक्षों को यह समझ आया कि इस संघर्ष का अंतिम समाधान केवल कूटनीति से ही संभव है।

फिलिस्तीन का प्रश्न: मूल विवाद के कारक

अरब-इजराइल संघर्ष का मुख्य केंद्र फिलिस्तीनी जनता की संप्रभुता और मानवाधिकार हैं। मूल विवाद चार प्रमुख स्तंभों पर टिका है:

1. **भूमि और सीमाएँ:** फिलिस्तीनी पक्ष 1967 के युद्ध से पूर्व की सीमाओं पर आधारित वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर एक अखंड, स्वतंत्र राज्य की मांग करता है।
2. **यरूशलेम की स्थिति:** इजराइल संपूर्ण यरूशलेम को अपनी 'अविभाज्य और शाश्वत राजधानी' मानता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भावी राज्य की राजधानी बनाने पर अड़े हैं।
3. **शरणार्थियों की वापसी का अधिकार:** 1948 और 1967 के युद्धों के बाद बेघर हुए लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके वंशजों (लगभग 56 लाख) का अपनी पैतृक भूमि पर लौटने का अधिकार। इजराइल इसे अपनी डेमोग्राफी (यहूदी बहुसंख्यक चरित्र) के लिए खतरा मानकर खारिज करता है।

4. **इजराइली बस्तियाँ:** 1967 के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 5 लाख से अधिक यहूदी नागरिकों को बसाया है। अंतरराष्ट्रीय कानून (चतुर्थ जिनेवा कन्वेंशन) के तहत इन बस्तियों को अवैध माना गया है, जो भौगोलिक रूप से किसी भी भावी फिलिस्तीनी राज्य को खंडित करती हैं।

शांति प्रयास: कूटनीतिक उपलब्धियां और सीमाएं

1. कैम्प डेविड समझौता (1978)

अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ।

- **परिणाम:** मिस्र इजराइल को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला अरब देश बना। इजराइल ने मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया।
- **सीमा:** इसमें फिलिस्तीनी स्वशासन की बात तो की गई, लेकिन उनके वास्तविक आत्मनिर्णय को दरकिनार कर दिया गया, जिसके कारण अरब जगत ने शुरुआत में मिस्र का बहिष्कार किया।

2. ओस्लो समझौते (1993 & 1995)

इजराइल और यासिर अराफात के नेतृत्व वाले 'फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन' (PLO) के बीच गुप्त वार्ताओं के बाद वाशिंगटन में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

- **परिणाम:** PLO ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार किया और इजराइल ने PLO को फिलिस्तीनी जनता के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 'फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण' का गठन हुआ और वेस्ट बैंक को ए, बी, और सी क्षेत्रों में विभाजित कर सीमित स्वशासन दिया गया।
- **विफलता का कारण:** इस समझौते में यरूशलेम, शरणार्थी और बस्तियों जैसे मूल मुद्दों को भविष्य की बातचीत पर छोड़ दिया गया। 1995 में इजराइली प्रधानमंत्री यित्झाक राबिन की दक्षिणपंथी यहूदी कट्टरपंथी द्वारा हत्या और हमास द्वारा किए गए आत्मघाती बम धमाकों ने ओस्लो प्रक्रिया को पूरी तरह पटरी से उतार दिया।

3. अब्राहम एक्वार्ड्स (2020)

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाया।

- **महत्व:** यह समझौता 'लैंड फॉर पीस' के बजाय 'पीस फॉर पीस' के सिद्धांत पर आधारित था। इसने इजराइल के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के द्वार खोले।
- **सीमा:** इसने अरब जगत के उस पारंपरिक रुख को तोड़ दिया कि 'इजराइल के साथ संबंध तभी सामान्य होंगे जब फिलिस्तीन राज्य बनेगा'। फिलिस्तीनियों ने इसे अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना, क्योंकि इसने मुख्य विवाद को हल किए बिना क्षेत्रीय शांति का आवरण तैयार किया।

वैश्विक महाशक्तियों एवं क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका

पश्चिमी एशिया में शांति और संघर्ष की दिशा केवल इजराइल और फिलिस्तीन के द्विपक्षीय संबंधों से तय नहीं होती, बल्कि यह वैश्विक महाशक्तियों (Global Superpowers) और क्षेत्रीय खिलाड़ियों (Regional Actors) के रणनीतिक हितों पर भी निर्भर करती है। इस संरचना को दो मुख्य स्तरों—वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर—पर समझा जा सकता है:

1. विश्लेषणात्मक ढांचा

शक्ति का स्तर	प्रमुख देश / संस्था	मुख्य रणनीतिक हित	अपनाई गई रणनीति / भूमिका
वैश्विक महाशक्ति	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	- इजराइल की सुरक्षा की गारंटी - ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा - ईरान के प्रभाव को सीमित करना	- अरब-इजराइल सामान्यीकरण (अब्राहम एक्कार्ड्स) - सुरक्षा परिषद में वीटो (Veto) का प्रयोग - वार्षिक सैन्य सहायता
वैश्विक महाशक्ति	रूस (Russia)	- भू-राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखना - पश्चिमी वर्चस्व को संतुलित करना	- सीरिया में सैन्य अड्डा और हस्तक्षेप - ईरान और इजराइल दोनों से समानांतर संबंध
वैश्विक महाशक्ति	चीन (China)	- ऊर्जा सुरक्षा और बीआरआई (BRI) मार्ग - आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव	- सऊदी-ईरान कूटनीतिक समझौता (2023) - आर्थिक निवेश और मध्यस्थता की छवि
वैश्विक निकाय	संयुक्त राष्ट्र (UN)	- मानवीय सहायता और शरणार्थी कल्याण - अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन	- UNRWA के जरिए राहत कार्य - सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (242, 338)
क्षेत्रीय शक्ति	ईरान (Iran)	- क्षेत्रीय वर्चस्व - इजराइल और अमेरिकी उपस्थिति का विरोध	'प्रतिरोध के अक्ष' (Axis of Resistance) का नेतृत्व - हमास, हिजबुल्लाह और हुथी समूहों को वित्तपोषण

शक्ति का स्तर	प्रमुख देश / संस्था	मुख्य रणनीतिक हित	अपनाई गई रणनीति / भूमिका
क्षेत्रीय शक्ति	सऊदी अरब (Saudi Arabia)	- इस्लामी जगत का नेतृत्व - आर्थिक विविधीकरण (Vision 2030)	'अरब शांति पहल' (2002) का नेतृत्व - दो-राष्ट्र सिद्धांत के बिना इजराइल से वार्ता पर रोक
क्षेत्रीय शक्ति	मिस्र एवं जॉर्डन	- सीमावर्ती सुरक्षा और शरणार्थी नियंत्रण - सिनाई व अक्सा मस्जिद का प्रबंधन	- इजराइल व हमस के मध्य प्राथमिक मध्यस्थता - गाजा सीमा (रफाह क्रॉसिंग) का नियंत्रण
क्षेत्रीय शक्ति	कतर (Qatar)	कूटनीतिक प्रासंगिकता और तटस्थता	- हमस के राजनीतिक कार्यालय को शरण देना - बंधक विनिमय और युद्धविराम वार्ताओं की मेजबानी

2. विस्तृत भू-राजनीतिक विश्लेषण

(क) वैश्विक महाशक्तियों का रणनीतिक रुख

- संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ऐतिहासिक रूप से इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य सहयोगी रहा है। वाशिंगटन का प्राथमिक उद्देश्य इजराइल की 'गुणात्मक सैन्य श्रेष्ठता' बनाए रखना है। अमेरिका ने 1978 के कैम्प डेविड और 2020 के अब्राहम एक्काईस में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई, किंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ प्रस्तावों पर वीटो पावर का प्रयोग करने के कारण कई बार उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं।
- रूस और चीन (उभरता हुआ बहुध्रुवीय प्रभाव): रूस सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति के आधार पर मध्य पूर्व में मजबूत बना हुआ है। दूसरी ओर, चीन ने मध्य पूर्व में आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराने में चीन की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्र में अमेरिका का कूटनीतिक एकाधिकार अब समाप्त हो रहा है।

(ख) क्षेत्रीय शक्तियों की ध्रुवीकृत भूमिका

- ईरान का 'प्रतिरोध का अक्ष' (Axis of Resistance): 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी अधिकारों के मुख्य संरक्षक के रूप में पेश किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमस और यमन में हुथी विद्रोहियों को वित्तीय व सैन्य मदद देकर ईरान इजराइल और अमेरिकी हितों के खिलाफ एक छद्म युद्ध (Proxy War) संचालित करता है।
- सऊदी अरब और खाड़ी देश: सऊदी अरब का रुख हमेशा से 'अरब शांति पहल (2002)' पर आधारित रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि इजराइल को पूर्ण मान्यता तभी मिलेगी जब 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य बनेगा। यद्यपि यूएई और बहरीन ने अब्राहम एक्काईस के तहत इजराइल से संबंध स्थापित किए, लेकिन सऊदी अरब ने फिलिस्तीन मुद्दे के हल के बिना सामान्यीकरण से दूरी बनाए रखी है।

- **मिस्र और कतर का मध्यस्थता मॉडल:** मिस्र भौगोलिक निकटता के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सुरक्षा वार्ताओं का केंद्र है, जबकि कतर अपनी तटस्थ विदेश नीति का उपयोग करके हमास के राजनीतिक धड़े और पश्चिमी देशों के बीच एक कूटनीतिक पुल के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान चुनौतियाँ

- **बस्तियों का निरंतर विस्तार:** वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र छोटे-छोटे द्वीपों में बदल चुके हैं, जिससे एक अखंड फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण भौतिक रूप से असंभव होता जा रहा है।
- **आंतरिक फिलिस्तीनी विभाजन:** वेस्ट बैंक में 'फतह' के नेतृत्व वाला कमजोर व भ्रष्ट माना जाने वाला 'फिलिस्तीनी प्राधिकरण' और गाजा में सशस्त्र संघर्ष करने वाला 'हमास' आपस में विभाजित हैं। एक एकजुट फिलिस्तीनी नेतृत्व का अभाव वार्ता में बड़ी बाधा है।
- **इजराइल में कट्टर-दक्षिणपंथी राजनीति:** इजराइल की घरेलू राजनीति का अत्यधिक दक्षिणपंथ की ओर झुकाव, जो दो-राष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है।
- **गैर-राज्य कलाकारों की उग्रता:** हमास और हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेट हमले और हिंसा कूटनीतिक वार्ताओं की गुंजाइश को समाप्त कर देते हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

- **दो-राष्ट्र सिद्धांत का पुनरुद्धार:** सभी बाधाओं के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय समुदाय (EU, UN, भारत, अरब देश) के लिए 1967 की सीमाओं के आधार पर दो राज्यों का निर्माण ही एकमात्र प्रासंगिक और न्यायसंगत समाधान है।
- **एक-राज्य समाधान (One-State Solution):** यदि दो-राष्ट्र सिद्धांत विफल होता है, तो भविष्य में एक ही राज्य का परिदृश्य उभर सकता है जहाँ यहूदियों और अरबों को समान नागरिक अधिकार दिए जाएँ। हालाँकि, इजराइल इसे अपने 'यहूदी चरित्र' के अंत के रूप में देखता है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा:** एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते की आवश्यकता है जिसमें ईरान, सऊदी अरब और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को एक साथ संबोधित किया जा सके।

निष्कर्ष

पश्चिमी एशिया में शांति की तलाश एक ऐसा कूटनीतिक सफर रहा है जो ऐतिहासिक त्रासदियों, टूटे हुए वादों और अधूरी संधियों से भरा पड़ा है। अरब-इजराइल संघर्ष केवल भू-भाग पर अधिकार की लड़ाई नहीं है; यह दो समुदायों की राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षाओं का टकराव है। ऐतिहासिक घटनाक्रम यह सिद्ध करते हैं कि सैन्य बल द्वारा किसी एक पक्ष को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। इजराइल ने 1948 से लेकर अब तक सैन्य श्रेष्ठता तो हासिल कर ली है, लेकिन वह अपनी सीमाओं पर स्थायी शांति और सुरक्षा हासिल करने में असमर्थ रहा है। दूसरी ओर, फिलिस्तीनी जनता ने अभूतपूर्व विस्थापन और दमन के बावजूद अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की मांग को जीवित रखा है।

अब्राहम एकाईस जैसे हालिया कूटनीतिक प्रयासों ने यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी कि फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार करके अरब-इजराइल संबंधों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। हालाँकि, हालिया हिंसक संकटों ने इस अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

जब तक फिलिस्तीनी प्रश्न के मूल कारणों—अर्थात् कब्जा, बस्तियों का निर्माण, शरणार्थियों का संकट और यरूशलेम की स्थिति—का समाधान नहीं होता, तब तक क्षेत्रीय शांति की कोई भी इमारत रेत पर बनी दीवार की भांति ढहती रहेगी।

अंततः, पश्चिमी एशिया में शांति की राह इजराइल की सुरक्षा चिंताओं की गारंटी और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार के अनूठे संतुलन से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब केवल वक्तव्यों तक सीमित न रहकर एक ठोस, समयबद्ध और बाध्यकारी कूटनीतिक रूपरेखा तैयार करनी होगी।

सुझाव एवं सिफारिशें

- **दो-राष्ट्र समाधान का पुनरुद्धार:** संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों (242 और 338) और 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वायत्त, संप्रभु और अखंड फिलिस्तीन राज्य का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
- **इजराइली बस्तियों के विस्तार पर तत्काल रोक:** अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वेस्ट बैक में अवैध यहूदी बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए इजराइल पर कूटनीतिक व आर्थिक दबाव बनाना चाहिए।
- **आंतरिक फिलिस्तीनी एकीकरण:** फतह और हमास के बीच राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित कर एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सर्वमान्य 'फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सरकार' का गठन किया जाए।
- **यरूशलेम हेतु विशेष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था:** यरूशलेम को एक साझा या विशेष दर्जा दिया जाए जहाँ तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों की रक्षा अंतरराष्ट्रीय देखरेख में हो।
- **समावेशी कूटनीतिक वार्ता :** शांति वार्ताओं में केवल अमेरिका की मध्यस्थता के बजाय संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, रूस, चीन और प्रमुख क्षेत्रीय देशों (सऊदी अरब, मिस्र, ईरान) के एक बहुपक्षीय मंच को शामिल किया जाए।

संदर्भ सूची

1. कपचान, सी. ए. (2010), *हाउ एनिमीज मेक पीस: द इमर्जेंस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. पारसी, टी. (2007), *ट्रेचर्स अलायंस: द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स*, येल यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. सैद, ई. डब्लू. (1994), *द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजेशन: द स्ट्रगल फॉर पैलिस्टिनियन सेल्फ-डिटर्मिनेशन, 1969-1994*, पैथियॉन बुक्स।
4. श्लाइम, ए. (2001), *द आयरन वॉल: इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड*, डब्लू. डब्लू. नॉर्टन एंड कंपनी।
5. टेसलर, एम. (2009), *ए हिस्ट्री ऑफ द इजराइली-पैलिस्टिनियन कॉन्फ्लिक्ट* (द्वितीय संस्करण), इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. संयुक्त राष्ट्र. (1967), *प्रस्ताव 242: द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट*, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आधिकारिक रिकॉर्ड।
7. संयुक्त राष्ट्र. (1973), *प्रस्ताव 338: सीजफायर इन द मिडिल ईस्ट*, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आधिकारिक रिकॉर्ड।